

Education News Group



एजुकेशन न्यूज ग्रुप



एमडीएस यूनिवर्सिटी : कई परिणाम जारी

अजमेर | एमडीएसयू ने एमएससी बॉटनी सेमेस्टर प्रथम व मास्टर इन योगा स्टडीज एंड देयर मैनेजमेंट सेमेस्टर थर्ड के परिणाम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर घोषित कर दिए। एमएससी बॉटनी सेमेस्टर प्रथम में कुल 100 विद्यार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए थे। इनमें से 92 उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं यानी 92 प्रतिशत परिणाम रहा है। मास्टर इन योगा स्टडीज एंड देयर मैनेजमेंट सेमेस्टर थर्ड में 18 में से 17 विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। कुल 94.44 प्रतिशत परिणाम रहा।

विद्यार्थी जहां हैं, उसी जिले से दे सकेंगे बोर्ड की परीक्षा

नई दिल्ली | सीबीएसई ने कोरोना संकट की वजह से गृह राज्यों में गए विद्यार्थियों को राहत दी है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि ऐसे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकते हैं। उन्हें जून के पहले हफ्ते में बताया जाएगा कि वे किस स्कूल से परीक्षा दे सकेंगे। 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई तक होंगी।

विभाग हो गए आवंटित, फिर भी नौकरी नहीं लापरवाही से उम्मीदवारों की नौकरियों पर संकट

विनोद मित्तल | जयपुर

कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड द्वितीय सीधी भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों की परेशानियां दूर नहीं हो रही। पहले विभाग और जिला आवंटन को लेकर विवाद हुआ। अब अभ्यर्थियों के सामने नई परेशानी खड़ी हो रही है।

गौरतलब है कि प्रशासनिक सुधार विभाग (एआरडी) ने चयनितों को जो विभाग आवंटित किए थे, वहां उनके पद ही नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला है सैनिक कल्याण विभाग का भी सामने आया है।

एआरडी ने सैनिक कल्याण विभाग को 26 चयनित आवंटित किए थे, लेकिन सैनिक कल्याण विभाग ने इनको यह कहते हुए वापस भेज दिया कि हमने तो पूर्व सैनिक मांगे थे, फ्रेशर नहीं। एआरडी ने पिछले दिनों 11,258 चयनितों को 111 विभागों का आवंटन किया था। इसमें सैनिक कल्याण विभाग को 26 चयनित आवंटित हुए। चयनित जब नियुक्ति के लिए पहुंचे तो उन्हें निराश लौटना पड़ा। सैनिक कल्याण

■ चयनितों को विभाग तो

आवंटित हो गए, लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जो नियुक्ति देने में आनाकानी कर रहे हैं। चयनितों को परेशान करने वाले विभागों की सूची तैयार की जा रही है।

-उपेन यादव, प्रवक्ता, राजस्थान
एकीकृत बेरोजगार महासंघ

विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि केवल पूर्व सैनिक मांगे थे। एआरडी ने फ्रेशर दे दिए। नियमों के अनुसार इस विभाग में पूर्व सैनिकों को ही रखा जा सकता है।

विभाग ने एआरडी को इस संबंध में पत्र लिखकर कहा है कि हमें फ्रेशर नहीं चाहिए। केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में तय हुआ था कि सैनिक कल्याण विभाग में 100 फीसदी कर्मचारी पूर्व सैनिक होंगे। पूर्व सैनिक नियमों को अधिक बेहतर तरीके से जानते हैं, जबकि फ्रेशर्स को नियमों की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने फ्रेशर्स दिए हैं, जो नियमों की जानकारी नहीं रखते हैं। इसी वजह से नियुक्ति में दिक्कत आ रही है।

अब छात्र गृह जिले में ही दे सकेंगे सीबीएसई परीक्षा

जयपुर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि अब छात्र अपने जिले में ही रहते हुए परीक्षा दे पाएंगे। इससे राजस्थान के हजारों छात्रों को राहत मिली है। कोटा, सीकर व जयपुर जैसे शहरों में कोचिंग के लिए आए छात्र कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से फिर से अपने घर चले गए थे। इसके बाद सीबीएसई ने शेष परीक्षाओं का एलान कर दिया था। इससे छात्रों को चिंता सता रही थी कि उन्हें फिर से संबंधित जिलों में लौटना होगा। अब नए आदेश के बाद वे अपने गृह जिले में रहते हुए शेष परीक्षाएं दे पाएंगे। वहीं जेईई मेन व नीट जैसी परीक्षाओं को लेकर भी एनटीए ने पहले ही सेंटर बदलने की सुविधा छात्रों को प्रदान कर दी थी। हालांकि सेंटर बदलने के लिए छात्र को अपने स्कूल से संपर्क करना होगा। वहां से सहमति मिलने के बाद ही छात्र अपने जिले में परीक्षा दे पाएगा।

असि. इंजीनियर के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई

जयपुर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) की ओर से आयोजित होने वाली जूनियर इंजीनियर की परीक्षा के उम्मीदवारों के पास अभी 18 दिन का समय बाकी है। यूपीएससी ने आवेदन की तारीख को भी बढ़ा दिया है। आवेदन के लिए 18 दिनों का अतिरिक्त समय अभी भी रहेगा। यूपीएससी 63 पदों के लिए यह एग्जाम आयोजित करवाएगा। डिफेंस, इरिगेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस सहित अन्य विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्ती की जानी है। यूपीएससी अपनी सभी परीक्षाओं की तारीख भी पांच जून को ही जारी करेगा। कोरोना वायरस के कारण यूपीएससी को भी अपने एग्जाम्स स्थगित करने पड़ गए थे। केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए यूपीएससी व एसएससी दो बड़ी एग्जाम एजेंसी हैं।

न्यू सेशन • देश के बड़े बिजनेस स्कूल्स व तकनीकी संस्थानों ने पढ़ाई के लिए की व्यवस्था

बैच में कैंपस आएंगे आईआईटी छात्र, सिलेबस में भी नहीं होगा कोई बदलाव

वर्तिका तोलानी | जयपुर

देश की आईआईटीज व बिजनेस स्कूल्स ने लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाले नए सेशन के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार 2019-2020 सेशन में 21 आईआईटीज में 1,99,399 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आईआईएम में यह आंकड़ा लगभग 11,000 है। इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई के भविष्य के बारे में जानने के लिए भास्कर ने आईआईटीज और बी-स्कूल्स से सेमेस्टर, एग्जाम्स, सिलेबस व प्लानिंग के बारे में जाना।

वेबएक्स एप्लीकेशन से आईआईटी रुड़की में पढ़ाई

आईआईटी रुड़की ने वेबएक्स एप्लीकेशन के माध्यम से क्लासेस शुरू की हैं। आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर अजित कुमार चतुर्वेदी का कहना है कि हमारी बड़ी प्राथमिकता है बच्चों को संक्रमण से बचाना इसलिए लॉकडाउन के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को तीन बैचेज में डिवाइड किया है। सबसे पहले बैच वन कैंपस में आया और एग्जाम देगा। इसके बाद अन्य बैच आएंगे। जैसे-जैसे हालात सुधरेंगे हम इस दिशा में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे।

आईआईएम में ऑनलाइन स्टडी

आईआईएम उदयपुर में नए बैच की शुरुआत 20-30 जून और सेकंड ईयर की क्लासेस 1-7 जून के बीच होती हैं। इस बार ये जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू हो सकते हैं। आईआईएम इंदौर ने भी क्लासेज ऑनलाइन शुरू की हैं। डायरेक्टर हिमांशु राय ने बताया कि सेमेस्टर व एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही होंगे।

एकेडमिक प्रोग्राम्स की अवधि कम

संस्थान ऑनलाइन क्लासेस से सिलेबस पूरा कर रहे हैं। क्लासेज देर से शुरू होने की वजह से कुछ संस्थानों द्वारा अन्य एकेडमिक प्रोग्राम्स की अवधि कम की जा रही है। आईआईएमए द्वारा आठ हफ्तों की इंटरशिप छह हफ्ते की कर दी गई है। किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा कोर्स के सिलेबस में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है।

सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए दो पारी में स्कूल चलाने की तैयारी

बंद पड़े स्कूल भवनों का उपयोग भी किया जाएगा

जयपुर| केंद्र सरकार स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइन तैयार करने में जुटी है। इसमें पांचवीं तक के बच्चों का 3 महीने तक अवकाश घोषित करने और छठी से स्कूल खोलने पर मंथन चल रहा है। राजस्थान में भी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग सतर्क है। प्रदेश में अभी 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है। इसलिए विभाग अभी जल्दीबाजी में नहीं है। अधिकारी कोरोना की परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। आने वाले दिनों में कोरोना को लेकर देश और प्रदेश में क्या स्थितियां रहेगी। उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने हालांकि रूपरेखा तैयार कर रखी है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय परिस्थितियों के आधार पर लिया जाएगा। इसमें अधिक नामांकन वाली स्कूलों को दो पारी में चलाने की भी तैयारी है। साथ ही एकीकरण से बंद हुए 20 हजार से अधिक स्कूलों के भवन खाली पड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बच्चों को बैठाने के लिए इन खाली पड़े भवनों का उपयोग हो सकता है। इन भवनों में नजदीक स्थित स्कूलों के बच्चों को बैठाया जा सकेगा। शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कोरोना को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्क है। बच्चों और अभिभावकों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

सीएम ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में दी शिथिलता

अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृतक राज्य कर्मचारियों के 71 आश्रितों को शिथिलता

भास्कर न्यूज | जयपुर

कोरोना संकट की घड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता से निर्णय लेते हुए मृतक राज्य कर्मचारियों के 71 आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति नियमों में शिथिलता दी है।



इससे इन मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को संबल मिलेगा।

गहलोत ने आयु सीमा, देरी से आवेदन करने, प्रशासनिक विभाग में पद रिक्त नहीं होने पर अन्य विभाग में नियुक्ति चाहने सहित अन्य कारणों से लंबित प्रकरणों में मानवीय आधार पर निर्णय लेते हुए आवेदकों के लिए नियुक्ति की राह आसान की है। मुख्यमंत्री इस अवधि में अनुकंपा नियुक्ति के विभिन्न कारणों से लंबित 489 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक

डेढ़ साल में 2208 को दी है अनुकंपा नियुक्ति

बीते डेढ़ साल में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के प्रकरणों में राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में नियुक्तियां दी है। अब तक 72 विभागों में मृतक राज्य कर्मचारियों के 2208 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। माध्यमिक शिक्षा में 749, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 252, पुलिस में 177, जलदाय विभाग में 116, वन विभाग में 106, पशुपालन विभाग में 80, सार्वजनिक निर्माण विभाग में 78 तथा जल संसाधन विभाग में 68 दी है।

विचार कर शिथिलता दे चुके हैं। अनुकंपा नियमों के तहत परिवार की परिभाषा में पुत्रवधू के पात्र नहीं होने के मामले में भी सीएम ने शिथिलता देते हुए अब तक चार प्रकरणों में पुत्रवधु को नियुक्ति देना मंजूर किया है।

हाईकोर्ट ने 7 माह बाद हटाई 1832 कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से रोक

टिड्डी हमले के मद्देनजर
सरकार ने मांगी थी राहत

भास्कर न्यूज | जोधपुर

प्रदेश में टिड्डी हमले से चिंतित राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने करीब 7 माह से कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक बुधवार को हटा दी। अब उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि भविष्य में याचिकाकर्ता का तर्क स्वीकार हुआ तो उस समय उन्हें नुकसान नहीं हो, इसके लिए सरकार पद बढ़ाएगी। मामले के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षकों के 1832 पदों के लिए 25 मई 2018 को आवेदन मांगे थे। इनमें 243 पद



टीएसपी क्षेत्र के लिए निर्धारित थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने 19 मई 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में टीएसपी एरिया को बढ़ाते हुए कुछ अन्य क्षेत्रों को भी शामिल कर दिया। इसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 24 अक्टूबर 2019 को हाईकोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।

प्री वेटरनरी टेस्ट के ऑनलाइन आवेदन पांच जून तक

बीकानेर | वेटरनरी विश्वविद्यालय के पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए राजस्थान प्री-वेटरनरी टेस्ट के ऑनलाइन आवेदन 5 जून तक किए जा सकते हैं। राजस्थान प्री-वेटरनरी टेस्ट के संयोजक प्रो. हेमन्त दाधीच ने बताया कि विश्वविद्यालय के संघटक तथा संबद्ध महाविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम वर्ष 2020-21 में प्रवेश के लिए आरपीवीटी 9 अगस्त, 2020 को जयपुर व बीकानेर केन्द्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए

विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rajuvas.org पर उपलब्ध हैं। टेस्ट में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान का मूल निवासी और आयु 31 दिसम्बर, 2020 तक न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को सीनियर हायर सैकेण्डरी (जीव विज्ञान, बायोटेक्नालॉजी) से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी इस वर्ष सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में शामिल हुए हैं एवं उनका परीक्षा परिणाम शेष है, वे भी इस टेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कोर्ट के आदेश पर चार साल बाद अभ्यर्थी मुख्य सूची में शामिल

अजमेर| राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कोर्ट के आदेश पर करीब चार साल बाद एक अभ्यर्थी को मोटर वाहन उपनिरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2013 की मुख्य सूची में शामिल किया है। आयोग ने बुधवार को इस विद्यार्थी का परिणाम वेबसाइट पर जारी किया।

आयोग सचिव आशीष गुप्ता ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एसबी सीडब्ल्यूपी नंबर 4681/2016 प्रकाश चौधरी

बनाम राज्य व अन्य में 14 अक्टूबर 2019 को आदेश पारित हुआ। इस की अनुपालना में मोटर वाहन उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के पूर्व घोषित परिणाम 07 अप्रैल 2016 के क्रम में याची अभ्यर्थी प्रकाश चौधरी, रोल नम्बर 102577, अपि जा (चयन वर्ग जीईएनएम) को प्राप्तांकों के आधार पर मुख्य मेरिट सूची में मेरिट क्रमांक 25.ए पर प्रतिस्थापित किया जाता है।

आयोग ने जारी किया वरिष्ठ अध्यापक- सामाजिक विज्ञान, संस्कृत शिक्षा का परिणाम

अजमेर| राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2018 की काउंसलिंग का परिणाम बुधवार शाम को जारी कर दिया गया। आयोग ने मुख्य और आरक्षित दोनों सूचियां मय कटऑफ मार्क्स वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। आयोग सचिव आशीष गुप्ता ने बताया कि परीक्षा की विचारित सूची पात्रता जांच के लिए 22 नवंबर 2019 को जारी की गई थी। इस विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 6 फरवरी 2020 को काउंसलिंग के माध्यम से कराई गई। पात्रता जांच और काउंसलिंग के बाद आयोग ने मुख्य और आरक्षित सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपने रोल नंबर चेक कर सकेंगे। साथ ही कटऑफ मार्क्स भी देख सकेंगे।

अगले महीनों में भी हो सकती है छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं

स्माइल प्रोजेक्ट में शिक्षकों के परफॉर्मेंस की हुई समीक्षा

उदयपुर | शिक्षा विभाग ऑनलाइन एजुकेशन को लंबे समय तक विकल्प के रूप में अपनाने पर जोर दे रहा है। करीब 2 महीने से चल रहे स्माइल प्रोजेक्ट के बाद शिक्षकों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बुधवार को हुई समीक्षा मीटिंग में शासन सचिव मंजू राजपाल ने शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण को लेकर जानकारी दी। जून के पहले सप्ताह में पहली से आठवीं कक्षा के शिक्षकों का मूल्यांकन होगा।

मीटिंग में सीबीईओ सहित विभाग के अन्य अधिकारी शामिल हुए। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत शिक्षकों के रिपोर्ट कार्ड पर

भी चर्चा हुई। सीडीईओ शिवजी गौड़ ने बताया कि जिले के स्टार शिक्षकों को लिस्टेड करते हुए नाम जारी किए हैं। इनमें अनीसा तेलात टिनवाला, दीपा तलदार, कीर्ति कुमारी, मंजू कुमारी सागिया, नीलम छाजेड़, प्रकाश चन्द्र त्रिवेदी, पुष्पा सुखवाल, रमेश चन्द्र शर्मा, रंजना शर्मा, रीता कोठारी, शिवकरण निमल शामिल हैं। आगामी सत्र प्रभावित ना हो इसके लिए विभाग शिक्षकों की ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सक्रियता बढ़ाने और विद्यार्थियों को जोड़ने पर जोर दे रहा है। हालांकि गौड़ का कहना है कि कनेक्टिविटी की समस्या के चलते अनुरूप परिणाम मिलने मुश्किल है।

डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी

कोटा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए यूजीसी ने सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटी शब्द का उपयोग रोकने से संबंधित कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि यूजीसी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे संस्थान जिन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का ही दर्जा प्राप्त है, वे भी संस्थान के नाम के साथ यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि यूजीसी के नियमानुसार गलत है।

ऐसे सभी संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि वे एक माह की अवधि में यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग रोक दें। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी संस्थान ईमेल एड्रेस पर तथा लेटर-हेड्स पर या प्रसारण के किसी भी माध्यम में यूनिवर्सिटी शब्द का उपयोग ना करें। 27 मई को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के नोटिफिकेशन में यूजीसी द्वारा विभिन्न राज्यों के कुल 127 उच्च शिक्षण संस्थानों जिन्हें डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, उनकी सूची भी जारी की गई है।

निशुल्क पाठ्य पुस्तकों वितरण 1 जून से

जोधपुर | राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक वितरण केंद्र बासनी तंबोलिया द्वारा शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 1 से 12 की निशुल्क पुस्तकों का पंचायत समिति (ब्लॉकवार) वितरण 1 जून से शुरू किया जाएगा। पाठ्य पुस्तक मंडल के स्थानीय केंद्र के मुख्य प्रबंधक सुनील कुमार गौड़ ने बताया कि 1 से 17 जून तक प्रथम चरण की पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। वितरण केंद्र से पुस्तकें लेने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन की पूरी पालना करनी होगी।

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक वितरण केंद्र बासनी तंबोलिया

सेमेस्टर सिस्टम में देरी से बढ़ेगी इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष के स्टूडेंट्स की परेशानी

जोधपुर| सेमेस्टर परीक्षा परिणाम में देरी का खमियाजा इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष के स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ सकता है। 26 मार्च को होने वाली पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं विश्वव्यापी महामारी कोरोना के कारण स्थगित कर दी गई थी। जबकि पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं नियमानुसार दिसंबर या जनवरी में हो जानी चाहिए थी, लेकिन सीनियर छात्रों के पांचवें सेमेस्टर के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम देरी से फरवरी में आने

के कारण चौथे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम भी देरी से 16 मार्च को आया। ऐसे में परीक्षाएं आगे होती गईं और फिर पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं होने के कारण छठे सेमेस्टर में प्रवेश नहीं हो सका और छठे सेमेस्टर की कक्षाएं व लैब नहीं लगी। अब समस्या यह है कि जून में महाविद्यालय खुलता है तो 1 वर्ष में स्टूडेंट्स को 4 सेमेस्टर की परीक्षाएं, जिनमें 3 सेमेस्टर की पढ़ाई शामिल है, देनी होगी।

संयुक्त निदेशक ने ई-मेल पर मांगी शिक्षकों की आपत्तियों को लौटाया

कहा- डीईओ की आईडी से प्राप्त आपत्तियों को ही वैध माना जाएगा

भास्कर संवाददाता/बांसवाड़ा

निदेशालय बीकानेर में वरिष्ठ अध्यापक से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए जारी होने वाली पात्रता सूचियों की आपत्तियों को ई मेल के बजाय डीईओ की आईडी से भेजने के आदेश से वरिष्ठ अध्यापक परेशान हो रहे हैं। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष गमीरचंद पाटीदार ने बताया कि निदेशालय स्तर पर तैयार हो रही वरिष्ठ अध्यापक से प्राध्यापक पद के लिए पदोन्नति की पात्रता सूची में आपत्तियां ऑनलाइन

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा की मेल आईडी पर कार्मिक द्वारा भेजने के आदेश जारी हुए। जिसमें निदेशालय द्वारा विभिन्न विषयों की वर्ष 2020-21 की डीपीसी के लिए पात्रता सूची निर्मित किए जाने के लिए कार्मिक की आपत्ति ऑनलाइन संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय की मेल आईडी पर 28 मई शाम 6 बजे तक ईमेल कर अपलोड करने को कहा गया। इस आदेश के साथ ही संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर का मैसेज भी लिखा हुआ वॉट्सअप पर प्रसारित

हुआ। जिसमें संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर मंडल उदयपुर की मेल आईडी jdeduudr@gmail.com वर्तमान में उपयोग में नहीं होने के कारण समस्त वरिष्ठ अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी केवल पात्रता संबंधित परिवेदना ही निदेशालय के निर्देशानुसार भरकर सलग्न दस्तावेजों के साथ नई मेल आईडी sen.jdeduudr@gmail.com पर भेजे। जिले के कई शिक्षकों ने आपत्तियां भेज दी, लेकिन उदयपुर ने डीईओ द्वारा ही प्राप्त मेल को वैध माना।

कोरोना ड्यूटी में लगे अध्यापकों का अतिरिक्त वेतन बढ़ाने की मांग उठी

परतापुर। शिक्षक संघ सियाराम ने कोरोना ड्यूटी में लगे शिक्षकों का अतिरिक्त वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

प्रदेश मुख्य महामंत्री ललित आर पाटीदार ने बताया कि प्रशासनिक प्रदेशाध्यक्ष सियाराम शर्मा ने पंजाब सरकार की तर्ज पर राज्य के कोरोना ड्यूटी में लगे शिक्षकों और कर्मचारियों की एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाए। जिलाध्यक्ष अशोक निनामा, जिला मंत्री नवीन जोशी और प्रवक्ता लोकेश

पटेल ने बताया कि संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में यह भी निवेदन किया कि शिक्षक एक वैकेशनल विभाग के कर्मचारी हैं परंतु उन्हें ग्रीष्मावकाश में भी कोरोना ड्यूटी में लगाया जा रहा है, जबकि प्रदेश में इनके अलावा चार लाख कर्मचारी अन्य गैर वैकेशनल विभाग के हैं। शिक्षकों की ग्रीष्मावकाश में कोरोना ड्यूटी के एवज में उपार्जित अवकाश देने की मांग करते हुए शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी कार्य से हटकर अन्य क्षेत्र में नहीं लगाने की भी मांग की है।

शारीरिक शिक्षकों ने प्रमोशन मांगा

बांसवाड़ा. शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर प्रमोशन की मांग की है। जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि राज्य में 40 से ज्यादा पद रिक्त है। इन्हें तुरंत प्रमोशन कर भरा जाए। साथ ही प्रथम श्रेणी व्यख्याता शारीरिक शिक्षक के 2007 के बाद से डीपी सी नहीं होने से कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हो पाया। योग्य कर्मचारी प्रमोशन से वंचित रहे गए जिनका रिटायरमेंट भी हो गया है। अध्यक्ष त्रिवेदी ने कहा कि सरकार शारीरिक शिक्षकों के साथ प्रमोशन में सौतेला व्यवहार कर रही है। अगल जल्द प्रमोशन नहीं हुआ तो फिर शारीरिक शिक्षक संघ को आंदोलन करना पड़ेगा।

भास्कर एक्सक्लूसिव • सागवाड़ा उपकोष कार्यालय में ऑडिटर ने पकड़ी गडबड़ी, 3 बिलों का भुगतान रोका साइबर चोरों ने सागवाड़ा उपकोष ऑफिस की फर्जी आईडी बनाकर बिलिंग भी कर दी

जयपुर फाइनेंस तक पहुंचा मामला, एनआईसी जयपुर की टीम जांच में जुटी

तनुज शर्मा | इंदौरपुर

जयपुर फाइनेंस तक पहुंचा मामला, एनआईसी जयपुर की टीम जांच में जुटी

साहू • कोविड में सरकार ने भुगतान बंद कर दिया था, इसलिए पैसा बच गया

बरबोदनिया पीईओ के अंतर्गत सैलेरी बिल को फेक आईडी से ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाया गया। सागवाड़ा उपकोष कार्यालय की ओर से प्रतिदिन बिलों का वेरिफिकेशन वरीयता के आधार पर चलता है। ऐसे में बरबोदनिया के टोकन नंबर 2529 के आधार पर बरबोदनिया 23700 का बिल प्रस्तुत हुआ। इसी में फेक आईडी एसटीओएसजीए का उपयोग हुआ था। इसी प्रकार टोकन नंबर 2530 से बरबोदनिया 23700 का बिल प्रस्तुत हुआ। तीसरा बिल

2531 बरबोदनिया स्कूल का 42250 का बिल उसी आईडी से जारी हुआ है। तीनों बिल कहीं भी वरीयता में नहीं थे। इसके कारण उपकोष अधिकारी मीतेश शाह के समक्ष ऑडिटर ने संदेह जताया। मामला देखकर उनके होश उड़ गए। सागवाड़ा उपकोष कार्यालय की फेक आईडी तैयार कर बिल ऑनलाइन प्रस्तुत हो गया। उन्होंने पूरे प्रकरण को जिला कोष कार्यालय को प्रस्तुत किया। जहां से तुरंत जयपुर जांच के लिए भेजा गया।

ऐसे समझें पूरी प्रक्रिया: चार कार्यालयों से ऑनलाइन ही गुजरता है बिल, सभी की अलग लॉगइन आईडी

किसी भी सरकारी कार्यालय और विभाग के खर्च के बिल प्रस्तुत होते हैं। इसके लिए उस विभाग के उच्चतम अधिकारी को डीडीओ पासब दिया है। इसके लिए उसे विशेष लॉगइन आईडी दी जाती है। इस आईडी के आधार पर संबंधित बिलों को ऑनलाइन चढ़ाया जाता है। ये बिल संबंधित विभाग से होकर ब्लॉक में पहुंचता है। जहां पर उपकोष कार्यालय के कर्मचारी एकाउंटेंट अपनी लॉगइन आईडी से बिलों को ऑनलाइन वेरिफिकेशन करता है। जहां से उपकोष अधिकारी अपनी लॉगइन आईडी के माध्यम से बिल अप्रूव कर ट्रेजरी ऑफिस में भेजा जाता है। कोष कार्यालय में भी एकाउंटेंट बिलों की जांच कर जिला कोष अधिकारी को प्रस्तुत करता है। ये बिल वहां से अप्रूवड होकर ईसीएस के लिए भेजा जाता है। जहां से जयपुर से अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन भुगतान बैंक खाते में पहुंचता है।

■ बरबोदनिया स्कूल के बिल वरीयता में नहीं होने के बावजूद पास होने के लिए आ गए। ऑडिटर ने देखने के बाद मुझे बताया। पूरे प्रकरण में फेक आईडी तैयार करने की कोशिश की गई है। साइबर का मामला होने के कारण जिला कोष अधिकारी को सूचना दी।
- मीतेश शाह, उपकोष अधिकारी सागवाड़ा

पहले कोषाधिकारी की आईडी चुराई, क्योंकि किसी भी विभाग की आईडी जिला कोष कार्यालय से ही बनती है, उसी से बनाई सागवाड़ा फेक आईडी

जिले में किसी भी विभाग की लॉगइन आईडी तैयार करने का पावर जिला कोष अधिकारी और सहायक जिला कोष अधिकारी के पास होता है। उनकी स्वयं की लॉगइन आईडी से ही उपकोष की लॉगइन आईडी बन सकती है। यानी, उप कोष या अन्य विभाग की लॉगइन बनाने के लिए जिला कोष अधिकारी या सहायक जिला कोष अधिकारी की लॉगइन आईडी जरूरी होती है। ऐसे में यह तय है कि इस पूरे मामले ने साइबर चोरों ने जिला कोष कार्यालय से आईडी पासवर्ड चुराए हैं। इन्हीं चुराए आईडी पासवर्ड से सागवाड़ा सब ऑफिस की फेक आईडी बनाई है। इससे ऑनलाइन बिल प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया गया है।

■ सागवाड़ा उपकोष कार्यालय की फर्जी आईडी बनने का मामला सामने आया है। इसकी जांच जयपुर फाइनेंस की ओर से कराई जा रही है। जल्द ही आईडी बनाने वालों का खुलासा हो जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- दौलतराम डामोर, जिला कोष अधिकारी जयपुर

बीमा योजना में संशोधन • कक्षा नर्सरी से आठवीं तक प्रति छात्र प्रीमियम 25 रुपए कर सहित निर्धारित

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में लाभ लेने के लिए जमा करवानी होगी प्रीमियम राशि

भास्कर न्यूज़ | राजसमंद

राज्य बीमा तथा प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) जयपुर ने विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में संशोधन किया है। राज्य के निजी स्कूलों, सरकारी, निजी कॉलेज, विश्वविद्यालयों, तकनीकी कॉलेज, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के दुर्घटना बीमा के लिए पूर्व में

संचालित विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में वित्तीय सत्र 2020-21 से आंशिक संशोधन किया है। उप निदेशक रमणलाल जयपाल ने बताया कि योजना के तहत राज्य के अनुदानित, गैर अनुदानित स्कूलों, सरकारी, निजी कॉलेज, विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की दुर्घटना में मौत अथवा शारीरिक क्षतियों की दशा में विद्यार्थियों के माता, पिता, संरक्षक, पति, पत्नी (वैध मनोनीत)

को बीमा आवरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना के विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इसके तहत कक्षा नर्सरी से आठवीं तक प्रति छात्र प्रीमियम 25 रुपए कर सहित निर्धारित है। इसका बीमा धन 50 हजार रुपए है। इसी प्रकार कक्षा 9 से 12 तक प्रति छात्र 100 रुपए प्रीमियम निर्धारित है, जिसका बीमा धन एक लाख रुपए है। सभी सरकारी, निजी

कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी, उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र 100 रुपए प्रीमियम निर्धारित है, जिसका बीमा धन दो लाख रुपए है। राज्य बीमा विभाग को प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से पॉलिसी एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी तथा पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व आगामी वर्ष के लिए प्रीमियम प्राप्त होने पर प्रीमियम प्राप्ति की दिनांक से नई पॉलिसी जारी की जा सकेगी।

आरोप • प्रथम ग्रेड अध्यापक ने व्यक्तिगत द्वेषता का आरोप लगाया

कुंवारीया : शिक्षक का आरोप, पीईईओ लगातार कोविड-19 में इयूटी लगा रहे हैं

राजसमंद | कुंवारीया राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पीईईओ पर इसी स्कूल के प्रथम ग्रेड अध्यापक ने व्यक्तिगत द्वेषता का आरोप लगाते हुए लगातार कोविड-19 की इयूटी लगाकर परेशान करने का आरोप लगाया। पीईईओ पर एक के बाद दूसरी इयूटी लगाकर परेशान करने का आरोप लगाया है। ऐसे में अध्यापक ने सीडीईओ, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर तक ज्ञापन, मेल भेजा है। अध्यापक का कहना है कि वह घर पर बीमार मां को समय नहीं दे पा रहा है।

कुंवारीया रसायन विज्ञान के लेक्चरर रेलमगरा निवासी नवनीत आगल का कहना है कि वे लगातार

23 मार्च से कोरोना काल में इयूटी कर रहे हैं। कुंवारीया स्कूल के कार्यवाहक संस्था प्रधान राकेश कुमार चपलोट पर इयूटी लगाकर उनको परेशान करने का आरोप लगाया। ज्ञापन में बताया कि 23 से 31 मार्च तक स्कूल में ऑनलाइन क्लास से सेवाएं दीं। 8 से 14 अप्रैल होम आइसोलेशन की निगरानी में इयूटी दी। 24 से 26 अप्रैल तक राशन कार्ड में सरकारी कर्मचारियों के नाम हटवाने की इयूटी दी। 27 से 30 अप्रैल तक कुंवारीया यादव मोहल्ले में सर्वे कार्य में इयूटी दी गई। 4 से 8 मई और 13 मई से 16 मई तक क्वारंटाइन सेंटर पर इयूटी दी गई। इसके बाद कुंवारीया तहसीलदार ने टपरियाखेड़ी इयूटी

लगाने के लिए अध्यापकों के नाम मांगे तब भी आगल का नाम भेजा गया। 22 मई से पुन राजसमंद-भीलवाड़ा के टपरिया खेड़ी बॉर्डर पर अनवरत इयूटी लगा दी गई। जबकि स्कूल कुल 25 स्टाफ में से बाहर के अध्यापकों को ग्रीष्म कालीन अवकाश के लिए कार्यमुक्त कर दिया। शेष 19 अध्यापकों को स्कूल में ही रखा गया। जबकि बीकानेर निदेशक के आदेशानुसार जिन टीचरों ने कोविड में इयूटी नहीं की है या कम इयूटी दी है। उनको ग्रीष्मकालीन अवकाश में लगाने का आदेश दिए। आगल का कहना है कि मां पुष्पा देवी को पांच महीने पहले सांड के सींग मारने से गिर गए थे। इससे मां की कूल्हे

आरोप निराधार है

■ कोविड-19 में पूरे स्टाफ को समान रूप से इयूटी लगाई। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया। मेरे पर व्यक्तिगत द्वेषता का आरोप निराधार है।

राकेश कुमार चपलोट, कार्यवाहक पीईईओ कुंवारीया।

■ मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। इस मामले की जांच करवाई जाएगी।

सुशील कुमार, एसडीएम राजसमंद।

की हड्डी टूट गई। पुष्पा देवी के सात ऑपरेशन हुए। उनका कहना है कि कोविड-19 में इयूटी आने के बाद मां को वॉकर पकड़वाकर चलने का अभ्यास नहीं करवा पा रहे हैं।

रा
प
रा
श
म
ध
ने
के
ह
ध
र

कोरोना इफेक्ट • विद्यार्थी घर बैठे पोर्टल पर देख सकेंगे क्रमोन्नत प्रमाण-पत्र, लॉकडाउन बाद स्कूल खुलने पर होंगे जारी

2.71 लाख विद्यार्थी बिना परीक्षा पास, 10वीं व 12वीं में प्रमोट 64318 छात्रों का प्रभावित हो सकता है रिजल्ट

भास्कर संवाददाता | नागौर

9वीं-11वीं : समग्र मूल्यांकन के आधार मिलेंगे नंबर

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जिले के 10 कक्षाओं के 2.71 लाख विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए पास कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है। जिले के 2906 सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8, 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में सीधे क्रमोन्नत किया है।

शिक्षा विभाग के जानकारों का कहना है कि 9वीं और 11वीं के

कक्षा नौवीं व 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनके समग्र मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 10 व 12 में क्रमोन्नत किया जाएगा। वहीं गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को पीएसपी पोर्टल के माध्यम से आगामी कक्षा में क्रमोन्नत कर पीएसपी पोर्टल से निर्धारित प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर उसे विद्यार्थियों को देना होगा। इसमें छात्रा प्रति मान्य नहीं होगा।

बोर्ड कक्षाओं में प्रमोट करने की यह प्रक्रिया 64318 विद्यार्थियों को पढ़ाई पर सीधे तौर पर असर डालेगी। अगले सत्र का बोर्ड परिणाम गिर सकता है। ऐसे में दोनों कक्षाओं के

विद्यार्थियों को बोर्ड में अच्छे अंक लाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। लॉकडाउन के चलते स्कूलें नहीं खुलने की वजह से छात्र-छात्राओं के क्रमोन्नत प्रमाण-पत्र

अटक गए हैं। दरअसल, सरकारी विद्यालयों में सत्र 2019-2020 में नियमित पढ़ रहे विद्यार्थियों के परिणाम व क्रमोन्नति प्रमाण-पत्र अब ऑनलाइन तैयार किए जा चुके हैं।

विद्यार्थी सीधे अपने प्रमाण-पत्रों को पोर्टल शाला दर्पण के जरिए देख सकते हैं। साथ ही अन्य जानकारी के लिए भी शाला दर्पण की वेबसाइट पर जा सकते हैं। क्रमोन्नत प्रमाण-पत्र विद्यार्थियों को स्कूल खुलने पर जारी किया जाएगा।

मिलेगा प्रमाण-पत्र

सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों को क्रमोन्नत करने का काम लगभग पुरा हो चुका है। साथ ही अब उनका परिणाम व क्रमोन्नति प्रमाण-पत्र भी तैयार हो गए हैं। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलने पर प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8, 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया है।

राशन कार्डों की जांच में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का शिक्षक संघ ने जताया विरोध

शिक्षक संघ शेखावत ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन

भास्कर संवाददाता/धौलपुर

प्रमोशन सूची में छूटे शिक्षकों के नाम जुड़ेंगे, शिक्षक संघ की आपत्ति के बाद संयुक्त निदेशक ने डीईओ को दिए निर्देश

प्रशासन की ओर से राशन कार्डों की जांच करने के लिए लगाई गई शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर शिक्षक संघ शेखावत ने विरोध जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर राशन कार्डों की जांच कार्य से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग की है।

संघ के प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने एक से अधिक, डुप्लीकेट राशन कार्ड एवं बोगस राशन कार्डों की जांच के लिए कोर ग्रुप, निगरानी दल, ग्राम विकास अधिकारी एवं पटवारियों की ड्यूटी लगाकर रिपोर्ट तीन दिन में देने के आदेश पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। शर्मा ने बताया कि इसमें अन्य कर्मचारियों को भी लगाया गया है, लेकिन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को मौखिक निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाकर कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। शर्मा ने कहा कि राशन कार्डों से संबंधित कार्य रसद विभाग एवं पंचायत विभाग का है, इसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाना गलत है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही विकास अधिकारी राजाखेड़ा ने मनरेगा की निगरानी कार्य में शिक्षकों

धौलपुर। तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति पात्रता सूची एवं व्याख्याता पद हेतु जारी पात्रता सूची में लगातार अशुद्धियों एवं पात्र शिक्षकों के नाम गायब होने की राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से भेजे ज्ञापन पर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा रिपुसूदन सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारियों से पात्र शिक्षकों के नाम बुधवार तक प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा बताया कि इससे पात्र शिक्षकों एवं वरिष्ठ अध्यापकों को राहत मिलेगी। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देशों में कहा है कि थर्ड ग्रेड से वरिष्ठ अध्यापक की 2020-2021 की डीपीसी के लिए अस्थायी पात्रता सूची जारी की गई थी। इसमें

की ड्यूटी लगाने पर शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार ने का विरोध कर शिक्षकों की कोविड-19 के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी शिक्षकों की ड्यूटी राशन कार्डों की जांच कार्य में लगाई गई है। जिलाध्यक्ष विशाल गिरि गोस्वामी एवं जिलामंत्री

प्राप्त सभी परिवेदनाएं आक्षेप, त्रुटियों को सुधार दिया गया था। फिर भी शिक्षक संघों की तरफ से आपत्ति आ रही हैं। इसलिए सूची में किसी शिक्षक का नाम छूट गया हो, यदि किसी का वर्ग गलत हो, विषय गलत है, नाम या जन्म तिथि में कोई संशोधन वांछनीय हो तो संबंधित कार्मिक पुष्टि के लिए साक्ष्य देकर अपना प्रार्थना पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को 27 मई तक प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक से प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के लिए जारी अस्थायी पात्रता सूची में किसी भी प्रकार की आपत्ति के लिए भरतपुर मण्डल कार्यालय की ईमेल आईडी पर निर्धारित फॉरमेट जो पात्रता सूची के साथ संलग्न है गुरुवार शाम 6 बजे तक प्रेषित किए जा सकते हैं।

अविनाश अग्रवाल ने कहा कि यदि कोविड-19 के अलावा शिक्षकों की ड्यूटी अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाई जाती है तो संगठन विरोध करेगा। शिक्षकों की ड्यूटी केवल शैक्षणिक कार्यों में ही लगाई जाए जिससे शिक्षकों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

नए सत्र में किताबें स्कूलों में तो आ जाएगी लेकिन देरी से मिलेगी

भास्कर संवाददाता | बाड़मेर

कोरोना महामारी के दौर में सरकारी विद्यालय बंद होने से लॉकडाउन में घर बैठे लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई ठप है। यह चिंता का विषय है कि सरकारी स्कूलों के छात्र नए सत्र 2020-21 में कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। इस बारे में अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

इधर, राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल कोरोना महामारी में भी बीते सालों की तरह ही पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहा है। कोरोना प्रकोप के चलते परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं। नतीजतन 10वीं और 12वीं बोर्ड की कक्षाओं को छोड़कर सभी को अगली कक्षाओं में बैठा दिया गया। साथ ही

गत सत्र एक तरह से खत्म हो गया। मार्च के दूसरे सप्ताह से ही स्कूल बंद हो गए थे। यानि 67 दिन से छात्र पढ़ाई से पूरी तरह से दूर रहे हैं। अभी स्कूलों में ग्रीष्मावकाश भी चल रहा है। इसके अलावा जुलाई में राजस्थान बोर्ड की शेष विषयों की परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। ऐसे में बच्चों के हाथों में किताबें पहुंचाने में वक्त लगेगा। जिला पाठ्य पुस्तक भंडार से ब्लॉक नोडल, यहां से पीईईओ और फिर अधीन स्कूलों में पुस्तकें वितरित होंगी। इस बार शिक्षकों को जिला मुख्यालय तक पुस्तकें लेने नहीं जाना होगा। विभाग ने जिले के 17 ब्लॉक मुख्यालयों पर पुस्तकें पहुंचाने का शेड्यूल भी जारी किया।

तैयारी • जिले भर में साढ़े नौ लाख से अधिक किताबें वितरित की जाएंगी, कक्षा 6 से 8वीं तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी लागू सरकारी स्कूलों में 1 जून से पुस्तक वितरण, दो चरणों में बच्चों तक पहुंचेगी किताबें

भास्कर संवाददाता/हनुमानगढ़

■ 1 जून से प्रथम चरण शुरू होगा, जून के अंतिम सप्ताह तक वितरित हो जाएंगी पुस्तकें

जिले के सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों का वितरण 1 जून से शुरू होगा। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार दो पुस्तकों का वितरण दो चरणों में किया जाना है। जिले भर के स्कूलों में डिमांड के हिसाब से करीब साढ़े नौ लाख पुस्तकें वितरित की जाएंगी। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं तक की सभी विद्यार्थियों को निशुल्क पुस्तकें दी जाएंगी। वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक के एससी-एसटी के छात्रों और ऐसे छात्र जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं हैं, उन्हें भी निशुल्क पुस्तकें दी जाएंगी। कक्षा पहली से

प्रथम चरण में 1 से 10 जून तक, दूसरे चरण में जून माह के अंतिम सप्ताह तक कक्षा एक से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को पुस्तकें दी जाएंगी। कक्षा 6 से 8वीं में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। वहीं विभाग से मिले निर्देशानुसार दो चरणों में पुस्तक वितरण शुरू होने जा रहा है। 1 जून से प्रथम चरण स्टार्ट होगा। बस्तों का बोझ कम करने के पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक से पांचवीं तक की निशुल्क पाठ्य पुस्तकें अब त्रैमासिक पुस्तिका भाग-1, भाग-2 और भाग-3 होंगी।

—राकेश सेठी, सहायक निदेशक एवं जिला प्रभारी।

पांचवीं तक त्रैमासिक निशुल्क पुस्तकें दी जाएंगी। प्रत्येक सरकारी स्कूल में गत सत्र की पुस्तकों में से 50 प्रतिशत पुस्तकें इस सत्र में उपयोग में लेनी हैं, जो विद्यार्थियों की ओर से लौटाई गई हैं। जिन विद्यार्थियों को विषयवार निशुल्क पुस्तकें दी जाएंगी, उन्हें त्रैमासिक निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित नहीं की जाएगी।

जिले भर के स्कूलों से साढ़े

नौ लाख से अधिक किताबों की डिमांड: कक्षा पहली से आठवीं तक 5 लाख 9 हजार 679 किताबें वितरित की जाएंगी। इसमें 4 लाख 95 हजार 518 किताबें सेकेंडरी, 9386 सेकेंडरी संस्कृत और 4775 किताबें प्रारंभिक मंदरसों को वितरित की जाएंगी। इसी तरह कक्षा 9वीं से 12वीं तक 4 लाख 70 हजार 85 किताबों में से 4 लाख

65 हजार 919 किताबें सेकेंडरी और 4166 किताबें संस्कृत एजुकेशन के लिए वितरित की जाएंगी।

कक्षा 6 से 8वीं तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू रहेगा: कक्षा 6 से 8वीं में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को निशुल्क नई पुस्तकें दी जाएंगी। कक्षा 9 में तृतीय भाषा की पुस्तकें माध्यमिक

शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ही लागू रहेंगी।

ख़ास बात यह है कि कक्षा 9 में 'राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा' और कक्षा 10 में 'राजस्थान का इतिहास' और संस्कृत विषय की लागू की नई पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। कक्षा 12 में 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2' लागू की गई है जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होगी। सभी विद्यार्थियों को यही पुस्तक नई उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं कक्षा 10 की समस्त विषयों की शेष पुस्तकें वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार ही रहेंगी। कक्षा 11 व 12 में भी इतिहास सहित कुछ विषयों की पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हैं। बाकी बचे विषयों की पुस्तकें एनसीईआरटी बेस्ड होंगी।

राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए स्कूलों से मांगे आवेदन

सीकर | माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने सत्र 2020-21 में 65वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का वार्षिक खेल पंचांग तैयार किया जाएगा। निदेशालय ने खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल के लिए विद्यालयों से आवेदन मांगे हैं। संस्था प्रधान 15 जून तक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के द्वारा आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन पत्र या संस्था की ईमेल sec.sportsbkn@yahoo.com पर भेज सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के उपनिदेशक (खेलकूद) प्रकाश चंद जाटोलिया ने बताया कि का प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरांत विद्यालयों को खेल प्रतियोगिता आयोजित करवाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शेष रहे खेलों का आवंटन मंगलवार रोस्टर पद्धति के जरिए किया जाएगा।

स्टूडेंट्स ने मेडिकल कॉलेजों में 7.5 लाख रुपए फीस वसूलने का मुद्दा ट्विटर पर उठाया

स्टूडेंट्स ने 30 हजार से ज्यादा ट्वीट किए

भास्कर संवाददाता | सीकर

राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में सरकारी सीटें बेचे जाने के विरोध में भविष्य के चिकित्सकों ने बुधवार को ट्विटर पर कैंपेन चलाया। 30 हजार से ज्यादा ट्वीट के जरिए सरकार के सामने अपनी परेशानी रखी। भावी चिकित्सकों का कहना है कि राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में 35 फीसदी मेरिटोरियस छात्रों से 7.5 लाख रुपए बतौर फीस गलत तरीके से वसूले जा रहे हैं। यह फीस विभिन्न संस्थानों की फीस से बेहद ज्यादा है। छात्रों ने लिखा कि सामान्य कट ऑफ से मात्र दो-तीन अंक कम रहने वाले प्रतिभावान छात्रों से प्राइवेट कॉलेज से भी ज्यादा 7.5 लाख रुपए फीस वसूलना न्यायसंगत नहीं है।

अमन शर्मा ने लिखा कि नौ महीने से आंदोलनरत मेडिकल छात्रों को अन्यायपूर्ण फीस से कोई राहत नहीं मिल रही। विकास ने लिखा कि सरकार उनकी क्यों नहीं सुन रही। नरेश ने लिखा कि अनावश्यक फीस छात्रों और उनके परिवार को हताश करती है। सरकार को थोड़ी मानवता दिखानी चाहिए। गौरतलब है कि राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में आईआईटी व आईआईएम से ज्यादा फीस वसूलने का मुद्दा सबसे पहले दैनिक भास्कर ने उठाया था। भास्कर की मुहिम के बाद ही यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। जहां कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। अभी तक सरकार ने इस मामले में फीस कम नहीं की है। इसलिए छात्र अब ट्विटर के जरिए अपनी परेशानी फिर से याद दिला रहे हैं।

कोविड-19: सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत

घर पहुंचे छात्र अपने जिले में ही दे सकेंगे परीक्षा

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी तेज कर दी है। इस दौरान बोर्ड ने देशभर के लाखों छात्रों को बड़ी राहत दी है जिसके अनुसार कोरोना संकट के कारण जो बच्चे अपने गृह प्रदेश चले गए हैं और अपने बोर्ड परीक्षा के सेंटर वाले जिले में नहीं हैं। ऐसे छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकेंगे। ■ शेष पेज-7

को विड-19 संकट के कारण हजारों बच्चे अपने गृह प्रदेश में चले गए थे, ऐसी स्थिति में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे विद्यार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने यह फैसला लिया है, कि ऐसे विद्यार्थी अपनी बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकते हैं।

-रमेश पोखरियाल निशंक,
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री,
भारत सरकार ”

राज्य बोर्ड सरकार के निर्देशों का कर रही है प्रतीक्षा

आरबीएसई के बाकी विषयों की परीक्षा के लिए छात्रों को करना होगा और इंतजार

ब्यूरो/नवज्योति, जरापुर

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है, लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) फिलहाल अपनी लंबित बोर्ड परीक्षाओं के दोबारा आयोजन को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं करना चाहता है। साथ ही राज्य सरकार से मिलने वाले निर्देशों की प्रतीक्षा में

हैं। बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में दो अहम विषयों की परीक्षा होनी बाकी है तो वहीं 12वीं के तीनों संकायों में कई विषयों की, लेकिन फिलहाल कोरोना से निपटने के बीच के तमाम उपायों के साथ बोर्ड इन लंबित परीक्षाओं के दोबारा आयोजन को लेकर तैयारी करने में लगा हुआ है।

पहले 12वीं का एग्जाम: बोर्ड पहले 12वीं की लंबित विषयों की परीक्षा कराने के मूड में है। इसके

पीछे कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख यह कि 12वीं के विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में दाखिले की दरकार है। इसके अलावा मौजूदा कोरोनाकाल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी 12वीं के पेपर कराने में ज्यादा आसानी के साथ कराई जा सकती है। 12वीं के जो विषय की परीक्षा अभी होना बाकी है उसमें छात्र संख्या 10वीं के मुकाबले काफी कम हैं।

केंद्रों को फिलहाल बना दिया क्वारंटाइन सेंटर

बोर्ड के अधिकतर परीक्षा केंद्रों को फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। ऐसे में बोर्ड को परीक्षा कराने के लिए 15 दिन का समय चाहिए। बोर्ड के सभी प्रश्न पत्र पुलिस थानों, कोषालय और पुलिस लाइन में सुरक्षित रखे हुए हैं।

आरपीएससी अध्यक्ष के घेराव की चेतावनी

कासं/नवज्योति, अजमेर

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष दीपक उप्पेती को पत्र लिखकर उन पर परीक्षाओं के आयोजन व परिणाम जारी करने में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। महासंघ ने आयोग अध्यक्ष के घेराव की चेतावनी भी दी है।

महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने पत्र में आरोप लगाया कि जब से उनकी नियुक्ति हुई है, तब से लगातार बेरोजगारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ना तो समय पर परीक्षा आयोजित हो पा रही है ना ही समय पर परिणाम आ रहे हैं। जो परिणाम

जारी किए जा रहे हैं, उनमें भी कई गड़बड़ियां छोड़ी जा रही हैं। अभी तक भर्तियों का कैलेंडर भी जारी नहीं किया गया है। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम भी अब तक नहीं आया है। यादव ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते आरपीएससी की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ और पारदर्शी नहीं किया गया तो वह साथियों के साथ घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा तिथि, परिणाम, इंटरव्यू के लिए कई बार धरना प्रदर्शन अनशन करना पड़ता है। इससे आरपीएससी की साख गिर रही है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि आयोग अध्यक्ष किसी भी बेरोजगार से नहीं मिलते हैं।

वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम जारी

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बुधवार को वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2018 के सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरपीएससी ने



वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 के सामाजिक विज्ञान विषय की प्रोविजनल लिस्ट गत वर्ष 22 नवम्बर को जारी की थी। प्रोविजनल लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसिलिंग के जरिए 6 फरवरी को हुई। काउंसिलिंग के बाद बुधवार को आयोग ने परिणाम जारी कर दिया। मुख्य सूची में टीएसपी क्षेत्र के 4 और नॉन टीएसपी क्षेत्र के 150 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। आयोग ने आरक्षित सूची भी जारी की है।

आपत्ति का आज अंतिम दिन

प्राध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा - 2018 के ग्रुप बी के विषयों की उत्तरकुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का गुरुवार को अंतिम दिन है। आयोग ने ग्रुप-बी के सामान्य ज्ञान सहित ऐच्छिक विषय राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, संगीत, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन व भौतिक विज्ञान की उत्तरकुंजियां वेबसाइट पर अपलोड की हैं। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नॉडल प्रश्न पत्र के अनुरार और प्रमाणिक पुरतकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही दर्ज करानी होगी। आयोग ने प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क सौ रुपये निर्धारित किया है।

बोर्ड की शेष परीक्षाओं पर निर्णय आज-कल में



कास/अजमेर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की शेष परीक्षाओं के आयोजन तिथि को लेकर चल रहा असमंजस दो-तीन दिन में दूर हो जाएगा। प्रदेश की विभिन्न जिलों में लॉकडाउन में काफी रियायतें मिलने के बाद बोर्ड प्रशासन ने परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियां तेज कर दी हैं।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. डीपी जारोली ने बताया कि चौथे लॉकडाउन के बाद अब धीरे-धीरे डेढ़-दो माह से

सरकार के निर्देश का इंतजार

राज्य में कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में भी राहत देने से परीक्षा केन्द्र बनाने के विकल्प खुलने लगे हैं। सरकार से लगातार परीक्षा संबंधी चर्चा जारी है। जैसे ही मुख्यमंत्री और

शिक्षामंत्री से निर्देश प्राप्त होंगे, वैसे ही बोर्ड परीक्षा की तिथियां घोषित कर देगा। परीक्षा कब करानी है, इसका अंतिम निर्णय सरकार को ही करना है। सरकार के निर्देश मिलने के बाद बोर्ड को परीक्षा तिथि घोषित करने और केन्द्र बनाने के लिए एक सप्ताह लगेगा।

उठावना / पुण्यतिथि / श्रद्धांजलि

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी कोरोना जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन में हम सभी अपने-अपने घरों में कैद के निधन, पुण्यतिथि, जन्मदिन अथवा शादी की वर्षगांठ आदि में नहीं हो सकते। ऐसे में आप उठावना / पुण्यतिथि / श्रद्धांजलि से प्रकाशित करवाकर अपनी संवेदना अथवा शुभकामनाएं प्रेषित

दसके लिए आ

राजकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया व नामांकन बढ़ाने को लेकर कोई गाइडलाइड नहीं

ब्यूरो नवज्योति/उदयपुर। प्रदेश भर के सरकारी विद्यालयों में नए सत्र की शुरुआत 1 मई से होती थी। वहीं प्रवेश प्रक्रिया नामांकन वृद्धि का कार्य भी मई माह में ही जोर पकड़ लेता था। इस बार लॉकडाउन के चलते अभी तक विभाग ने गाइडलाइन ही जारी नहीं की है।

प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पर चल रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी लॉकडाउन से पहले ही ऑफलाइन फॉर्म ले गए थे, लेकिन अभी तक उनकी लॉटरी नहीं निकाली गई है। आरटीई के तहत प्रवेश को लेकर भी अभी शिक्षा विभाग ने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया 29 फरवरी से ही शुरू हो गई थी। डाउन के चलते बहुत से अभिभावक प्रवेश फार्म जमा नहीं करवा पाए थे।

नामांकन का कार्य भी होगा प्रभावित : प्रदेश भर के सरकारी विद्यालयों में 1 मई से ही नामांकन बढ़ाने को लेकर अध्यापक घर-घर दस्तक देने शुरू कर देते हैं। नामांकन बढ़ाने के लिए रैलियां, नामांकन रथ, सरपंच, पंच, स्थानीय भामाशाहों और गांव के प्रबुद्धजनों का सहयोग लेकर नामांकन बढ़ाया जाता है। इस बार प्रवेश प्रक्रिया और नामांकन सहित अन्य सभी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं।

मामले में अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही प्रवेश प्रक्रिया को लेकर गाइडलाइन जारी होगी। इसके उपरान्त हम शिक्षकों की टीमों तैयार कर नामांकन बढ़ाने और प्रवेश प्रक्रिया शुरू करवाने का कार्य करेंगे। अभी तक आरटीआई के तहत भी प्रवेश को लेकर विभाग से आदेश नहीं मिले हैं।

बोर्ड परीक्षा तिथियों का ऐलान नहीं होने से विद्यार्थी असमंजस में

ब्यूरो नवज्योति/उदयपुर। राजस्थान बोर्ड की 10वीं, 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान अभी तक नहीं हो सका है। परीक्षाओं और रिजल्ट को लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार ने मई के पहले सप्ताह में ऐलान किया था कि सीबीएसई के आधार पर राजस्थान शिक्षा विभाग भी तय करेगा कि छात्रों की शेष परीक्षाएं कहां जाएं या बिना परीक्षा के ही पास कर दिया जाए, लेकिन सीबीएसई ने मई के दूसरे सप्ताह में

शेष परीक्षा की तिथियां जारी कर दी, लेकिन राजस्थान बोर्ड की ओर से इस बारे में छात्रों को अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई। कुछ समय पहले शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह छोटसरा ने सभी जिला शिक्षाधिकारियों की वीसी में इस बात का संकेत दिया था कि शेष परीक्षाओं के बारे में 17 मई के बाद फैसला लिया जा सकता है, लेकिन इस पर अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। माना जा रहा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण सरकार को परीक्षाओं के बारे

रिजल्ट में हो सकती है देरी

वीसी के बाद अधिकारियों ने बताया था कि शेष परीक्षाएं आयोजित कराने के 20 दिन बाद ही रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन जब अभी तक शेष परीक्षाओं की डेटशीट जारी नहीं हुई तो रिजल्ट की बात करना बेमानी होगी। संभावना है कि बोर्ड अगले एक सप्ताह में शेष परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर देगा, जिससे जल्द से जल्द परीक्षाएं शुरू हो सकें। 12वीं कक्षा की भूगोल, मनोविज्ञान, गणित, आईटी, गृहविज्ञान, संस्कृत साहित्य, व्यवसाय अध्ययन, चित्रकला, अंग्रेजी साहित्य और कुछ अन्य विषयों की परीक्षाएं बाकी हैं। वहीं 10 वीं में गणित, सामाजिक विज्ञान, आईटी, कृषि और कुछ अन्य विषयों की परीक्षाएं शेष हैं।

में फैसला लेने पर देरी हो रही है। वहीं सीबीएसई 12वीं की शेष परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच कराने की डेटशीट भी जारी की जा चुकी है।

इनका कहना है

शिक्षा राज्यमंत्री की दुधवार को वीसी थी। इसमें उन्होंने परीक्षा शुरू करने की तिथियां को लेकर फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया है।

शिवजी गौड़, संयुक्त निदेशक माध्यमिक

अब छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को होगी रोजगार परक परीक्षा



न्यूज सर्विस/नवज्योति, भीलवाड़ा

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से संचालित विद्यालयों में अब कक्षा 6 से छात्र-छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें कक्षा 6 से 11 तक के विद्यार्थी शामिल किये जायेंगे। हालांकि कक्षा 10 व 12 के छात्रों को सीबीएसई द्वारा पहले ही रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने की

तीन वर्गों में बांटी गई कक्षाएं

भीलवाड़ा। छात्र-छात्राओं को कक्षा के अनुसार तीन वर्गों में बांटा गया है। पहले में कक्षा 6, सात व आठ के विद्यार्थी, दूसरे वर्ग में 9 व 10 वीं तथा तीसरे वर्ग में 11 व 12 के छात्र छात्राएं होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर छह से आठवीं तक के छात्रों के लिये आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ब्यूटी एण्ड वेलनेस, डिजाइन, फाइनेंशियल आदि सिखाया जायेगा। कक्षा 6, 7 व आठ में किसी एक कक्षा स्कूल संचालक स्किल बेस्ड कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं। फिर विद्यार्थी अगली कक्षाओं में नियमित कर सकेगा। इसमें विद्यार्थियों की रुचि का ध्यान भी रखा जायेगा।

व्यवस्था की थी। नौवीं व 10 वीं के छात्र छात्राओं को रिटेल, आईटी, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, बैंकिंग, इश्योरेंस आदि सिखाया जायेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कम उम्र में

ही रोजगार के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिये प्रेरित करना है। स्किल बेस्ड कोर्स जो पहले 12 के बाद छात्र छात्राएं करते थे। उसका एक इंटीग्रेटेड कोर्स छोटी कक्षाओं के लिये जोड़ दिया है।

मुख्यमंत्री ने दी अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में ढील

जयपुर @ पत्रिका . मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संकट में अनुकंपा नियुक्ति नियमों में शिथिलता प्रदान की है, जिससे 71 मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति मिल सकेगी।

गहलोत ने आयु सीमा, देरी से आवेदन करने, प्रशासनिक विभाग में पद रिक्त नहीं होने पर अन्य विभाग में नियुक्ति चाहने सहित अन्य कारणों से लंबित प्रकरणों में आवेदकों के लिए नियुक्ति की राह आसान की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने डेढ़ वर्ष में विभिन्न कारणों से लंबित 489 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। चार प्रकरण ऐसे हैं जिनमें अनुकंपात्मक नियुक्ति नियमों के तहत परिवार की परिभाषा में पात्र नहीं होने के बावजूद विधम पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर पुत्रवधू को नियुक्ति देने की मंजूरी दी गई है। डेढ़ साल में अब तक 72 विभागों में 2208 को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है।

टिड्डी हमले को देखते हुए हाईकोर्ट ने रोक हटाई

1832 कृषि पर्यवेक्षकों के पदों पर नियुक्ति के निर्देश

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में टिड्डी के हमले को देखते हुए 1832 कृषि पर्यवेक्षकों के पदों पर सशर्त नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। यह नियुक्तियां कोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी और इसका उल्लेख नियुक्ति पत्र में किया जाएगा।

न्यायाधीश अरुण भंसाली ने याचिकाकर्ता भरतलाल मालवीय सहित अन्य द्वारा दायर याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए कहा कि टिड्डी हमले को देखते हुए यह समय की जरूरत है कि कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाया जाए। हाईकोर्ट ने 24

अक्टूबर, 2019 को कृषि पर्यवेक्षकों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी। याचिकाओं में कहा गया था कि राज्य सरकार ने कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती के लिए 25 मई, 2018 को विज्ञापित प्रकाशित की, जिसमें अतिरिक्त टीएसपी एरिया को शामिल किया गया, लेकिन सरकार ने टीएसपी एरिया के आरक्षण प्रावधानों को लागू नहीं किया, जिससे इस एरिया में रहने वाले लोगों को कम पदों पर नियुक्तियां मिलेंगी। महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने रोक हटाने का प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कहा कि टिड्डी हमले के आसन्न संकट को देखते हुए कृषि पर्यवेक्षकों को नियुक्तियां दी जानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कोर्ट ने जब रोक लगाई, तब तक चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण

हो चुका था। सिंघवी ने कहा कि यदि याचिकाएं अंतिम तौर पर स्वीकार कर ली जाती हैं तो सरकार टीएसपी एरिया के लिए पद बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से याचिकाकर्ताओं के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। सरकार ने 1832 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति जारी की थी, जिनमें 1589 पद नॉन टीएसपी तथा 243 पद टीएसपी एरिया के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे। एक्लपीठ ने सरकार की सहमति को देखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार होने की स्थिति में सरकार को पद बढ़ाने होंगे और चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जाए कि यह याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों का हाल, प्रथम श्रेणी में नहीं हुई पदोन्नति

पदोन्नति की उम्मीद में बीत गए 13 साल

नियमों में उलझा मामला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बीकानेर. स्कूल स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने वाले उन शिक्षकों की उपेक्षा हो रही है, जो एक विद्यार्थी में खेल का जज्बा पैदा करता है। प्रदेश में 250 से अधिक शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, वहीं बीते 13 साल से प्रथम श्रेणी पदों पर पदोन्नतियां ही नहीं हुईं। बताया जा रहा है कि इसके लिए पद सृजन का कार्य भी नहीं हुआ, सेवा नियमों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। अभी लंबे समय से इन शारीरिक शिक्षकों की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में अटकी है।

नहीं बढ़ेगा वित्तीय भार : शारीरिक शिक्षक संगठनों के अनुसार यदि सरकार शारीरिक शिक्षकों को प्रथम श्रेणी में पदोन्नति देती है, तो सरकार पर किसी तरह वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा। सरकार को महज पद ही देना होगा, इन शिक्षकों को वेतनमान (ग्रेड पे) का पूरा लाभ पहले से ही मिल रहा है। सरकार ने उन स्कूलों में ही प्रथम श्रेणी के शारीरिक शिक्षक लगाने की घोषणा की है, जहां 750 विद्यार्थी होंगे। उसी

यह है स्थिति

वर्ष 2007 से प्रथम श्रेणी शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई। इसके चलते प्रदेश में 250 पद प्रथम श्रेणी के रिक्त पड़े हैं। इसके अलावा उप जिला शिक्षा अधिकारी के करीब 30 पद, जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा के चार पद, उपनिदेशक शारीरिक शिक्षा के तीन पद बीते कई साल से रिक्त पड़े हैं। पदोन्नति नहीं होने से शारीरिक शिक्षक जिस पद पर नियुक्त होते हैं, उसी पद से उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। यही नहीं, शारीरिक शिक्षा के उपनिदेशक तक के पदों पर सरकार ने 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरने का नियम निर्धारित कर रखा है, लेकिन सीधी भर्ती कभी हुई ही नहीं।

गणना के आधार पर प्रदेश में 250 पद रिक्त पड़े हैं। वहीं उच्च प्राथमिक स्कूलों में 105 विद्यार्थी होने जरूरी होंगे, जहां पीटीआइ लगाया जाए।

मिलनी चाहिए पदोन्नति

शारीरिक शिक्षक बीते लंबे समय से अपनी पदोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन मामला सरकार के पास नियमों में उलझा पड़ा है। शारीरिक शिक्षकों को प्रथम श्रेणी में पदोन्नति देने से सरकार पर किसी तरह वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा, केवल ग्रेड ही तो देना है, इसको लेकर नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए।

-सुरजीत सिंह नेहरा,
प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ

प्रक्रिया चल रही है

प्रथम श्रेणी शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो रही है, इसके लिए नियमों में संशोधन नहीं था। इस कारण अटकी है। अभी मामला सरकार के पास है और नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है।

-नूतनबाला कपिला, संयुक्त निदेशक, मा.शिक्षा निदेशालय, बीकानेर

जिले में पहला चरण 11 जून तक चलेगा,
नोडल अधिकारियों को मिलेंगी किताबें

एक जून से वितरित होंगी निशुल्क पाठ्य पुस्तकें

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

बीकानेर. जिले के सभी राजकीय विद्यालयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का पहला चरण एक जून से शुरू होगा। इसमें जिले में 11 जून तक पुस्तक वितरण किया जाएगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान राजकुमार शर्मा ने बुधवार को कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार नोडल प्रभारी रुटचार्ट के अनुसार जयनारायण व्यास कॉलोनी स्थित राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल कार्यालय में पहुंच कर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।

इसके लिए स्टॉक रजिस्टर एवं संस्था प्रधान की मोहर के साथ स्वयं नोडल अधिकारी को ही पहुंचना होगा।

यूं चलेगा ब्लॉकवार कार्यक्रम

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण एक व दो जून को नोखा ब्लॉक में चलेगा। इसी तरह 3 जून को पांचू, 4 व 5 जून को श्रीडूंगरगढ़, 5 व 6 जून को बीकानेर, 8 से 9 जून को खाजूवाला, 9 व 10 जून को लूणकनसर एवं 11 जून को कोलायत ब्लॉक के निर्धारित नोडल केन्द्रों पर पुस्तकें मिलेंगी।

सीबीएसडी की जारी हैंडबुक का करें उपयोग

ऑनलाइन पढ़ाई: साइबर खतरों के चलते अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की चेतावनी



एक्सक्लूसिव

कृष्ण चौहान
rajasthanpatika.com

श्रीमंगलपुर, कोरोना महामारी की वजह से देशभर में शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन हो रही है। अभिभावक जिस मोबाइल को हाथ लगाने से ही बच्चों को रोक कर रहे हैं, उसी मोबाइल पर अध्ययन का साग दरोमदार आ गया है। यहाँ तक की अभिभावकों और शिक्षकों की भी अध्ययन, नोट्स व टेस्ट के लिए मोबाइल पर निर्भरता बढ़ गई है। सीबीएसडी ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन के समय में

इन खतरों से रहें सावधान, सजगता से करें पढ़ाई

1. साइबर बुलिंग

सुरक्षा मैनुअल में कहा है कि साइबर बुलिंग साइबर खतरों में से एक है जिनका सामना विद्यार्थी कर रहे हैं। इसमें इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अशुद्ध, घटिया, तक्रलीकदेह, रंदिश या इमेल भेजकर किसी को जानबूझकर रंग रिक्त जता है। इससे बचने के लिए विद्यार्थी केवल अपनी लॉगिन आईडी के साथ ही ऑनलाइन जुड़े रहें व ऑनलाइन न रहें।

तमाम खतरों से बचने के लिए एक गाइड लाइन जारी की है। इसमें डिजिटल नागरिकता के नौ आयामों डिजिटल फुटच, सखरता, संवाद, शिष्टाचार, स्वास्थ्य, कुशलश्रेम, अधिकार, स्वतंत्रता तथा जवाबदेही और कानून को शामिल किया है।

2. साइबर धमि

साइबर धमि एक बढ़ता साइबर खतरा है जो किशोरावस्था के विद्यार्थियों को अधिक प्रभावित करता है। इसमें अपराधी की ओर से जाली अकाउंट बनाकर बच्चे जैसा व्यवहार करता है तथा शोषण या बोन उतपीड़न के उद्देश्य से विद्यार्थियों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित किए जाते हैं।

अभिभावकों की भी रहेगी भूमिका

1. मोबाइल व लेफ्टॉप पर पढ़ाई अपनी देखरेख में करवाएं।
2. मोबाइल की बैकअप हिस्ट्री से मॉनिटरिंग करें व नजर रखें।
3. मोबाइल डाटा कोरी व अन्य हार्डवेयर से बचने के लिए पढ़ाई के

3. रिमोट पोर्नोग्राफी से सतर्कता

सीबीएसडी की जारी हैंडबुक में कहा गया है कि 14 साल से 18 साल के किशोर विद्यार्थी इसके सबसे बड़े शिकार होते हैं और इसी आयु वर्ग के टीनेजर्स इस काम को सबसे ज्यादा अंजाम देते हैं। इसमें बताया है कि कोई भी व्यक्ति ईमेल में, संवादों को तोड़ लेने पर या बात न करने पर भी ऐसा कर सकता है।

अलावा डाटा खर्ची पर पारबंदी लगाएं।

4. सोशल मीडिया पर विशेष सावधानी बरतें, बच्चे की ओर से शेयर करने वाली जानकारी और सूचनाओं से अवगत रहें।

4. ऑनलाइन खेलों से नुकसान

अक्सर देखा जा रहा है कि विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन खेल डाउनलोड करने के साथ स्पैम, वायरस, हैबपूरी सॉफ्टवेयर साथ में डाउनलोड हो जाते हैं जो कि विद्यार्थियों के कंप्यूटर, मोबाइल फोन या गेमिंग कंसोल को फ्रीक्वेंट रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए बोर्ड ने कहा है कि भूलकर भी

अवैध गेम और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने चाहिए।

फैक्ट फाइल

- किले में कुल विद्यार्थी-3019
- प्र.व उ.प्र. स्तर के विद्यार्थी-291284
- म.व उ.प्र. स्तर के विद्यार्थी-117542
- किले में कुल विद्यार्थी-408826

कर्मचारी में ऑनलाइन शिक्षण के लिए विद्यार्थी डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट, सर्वे इंजन, वेबसाइट आदि के इस्तेमाल की पूरी जानकारी के अभाव में बच्चे साइबर खतरों को कुत्ता न दें। इसके लिए पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों और अभिभावकों का बिना डरे सतर्क व सजग रहना बेहद जरूरी है। सीबीएसडी ने साइबर सुरक्षा मैनुअल सभी विद्यार्थियों के लिए लाभाध्यक है। -भूपेन्द्र शर्मा, सहसंचालक, शिक्षा की सेवा केंद्र माध्यमिक शिक्षा, श्रीमंगलपुर

अभिभावकों को आरटीई के शेड्यूल का इंतजार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

जयपुर. प्रदेश के स्कूलों में राइट टू एजुकेशन (आरटीई) एक्ट की सीमा एक लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख किए जाने के बाद अभिभावक शेड्यूल जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल, शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 17 मई के बाद इसे जारी करने कहा था। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अगले हफ्ते तक शेड्यूल जारी किया जा सकता है। अभी कैबिनेट एरिया और टाइम फ्रेम को लेकर प्रक्रिया

चल रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल अप्रैल में आरटीई का शेड्यूल जारी किया गया था।

ऑनलाइन आवेदन

पिछले साल की तरह आवेदन इस बार भी ऑनलाइन होंगे। आरटीई पोर्टल पर सीबीएसई और आरबीएसई के लगभग 38 हजार स्कूल रजिस्टर हैं। गौरतलब है कि 6 अप्रैल, 17 को पिछली सरकार ने आय सीमा को 1 लाख कर दिया था। हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2.50 लाख तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

संस्कृत विवि में शुरू होंगे नए पाठ्यक्रम

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

जयपुर. जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय नए शैक्षणिक सत्र से जर्मन भाषा के कोर्स के साथ ही संस्कृत भाषा के लिए नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करेगा। इस संबंध में कुलपति डॉ. अनुला मौर्य ने बुधवार को ऑनलाइन बैठक के दौरान शिक्षकों और अधिकारियों को निर्देश दिए। शैक्षणिक परिसर के निदेशक डॉ. के. सांबशिवमूर्ति ने बताया कि कुलपति ने स्पष्ट किया

कि सरकार के निर्देशों के अनुसार विवि. की परीक्षाओं के आयोजन पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुलपति ने विश्वविद्यालय को यूजीसी से आर्थिक अनुदान के लिए आवश्यक नैक मूल्यांकन की कार्ययोजना तैयार करने के लिए डॉ. सुभाष शर्मा को संयोजक नियुक्त किया। डॉ. सांबशिवमूर्ति ने बताया कि विश्वविद्यालय में नए सत्र में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसी सत्र से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाएगा।



नियमों के फेर में उलझे प्रदेश के चार हजार से अधिक वाणिज्य स्नातक शिक्षक

25 साल से अधूरी है प्रमोशन की आस



एक्सक्लूसिव

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

लक्ष्मणगढ़, राजस्थान का शिक्षा विभाग पांच वर्षों में हजारों शिक्षकों को पदोन्नति की खुशियां दे चुका है। वहीं प्रदेश के चार हजार से ज्यादा वाणिज्य स्नातक शिक्षक पिछले 25 वर्षों से द्वितीय श्रेणी अध्यापक बनने का ही इंतजार कर रहे हैं।

रोचक बात यह है कि इन शिक्षकों के कई वर्षों बाद तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्त शिक्षक इन्से कनिष्ठ होने के बावजूद दो-दो बार पदोन्नति पा चुके हैं। कारण चाहे जो भी हो पर इतने वर्षों बाद भी इन शिक्षकों का प्रमोशन नहीं होने से विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न मंडलों में वर्ष 2020-21 की डीपीसी प्रक्रिया



शुरू हो चुकी है। ऐसे में वाणिज्य स्नातक शिक्षक एक बार फिर इस आस में हैं कि उन्हें भी इस बार पदोन्नति मिल जाए।

इस संबंध में राजस्थान वाणिज्य शिक्षा संघर्ष समिति ने शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटसरा को ज्ञापन भेज कर पदोन्नति का हक दिलाने की मांग की है।

सभी तृतीय श्रेणी अध्यापकों का उनके स्नातक के विषयानुसार बंटवारा कर दिया। यह बंटवारा गणित, विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान आदि छह विषयों में किया गया। इन विषयों के अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा एवं मिडिल स्कूल दोनों में पद भी दिए गए, जबकि बीकॉम डिग्रीधारी

यह है
मामला

राजस्थान शिक्षा अधिनियम 1971 की पालना करते हैं इन शिक्षकों का प्रमोशन बहुत पहले हो जाता, लेकिन विभाग ने 18 जुलाई 2008 को नियमों में संशोधन कर

शिक्षकों को किसी भी विषय में शामिल नहीं करने से इनके प्रमोशन बंद हो गए। मामला न्यायालय में जाने पर 24 मार्च 2015 को शिक्षा विभाग ने इन्हें सामान्य विषय का शिक्षक मानकर मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन शुरू कर भी दिया, लेकिन पदों की कमी के चलते हर वर्ष यह प्रमोशन बहुत कम संख्या में होती है। यही कारण है कि 25 वर्षों से तृतीय श्रेणी पद पर कार्यरत ये शिक्षक अभी तक प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं।

न भर्ती में मौका,
न पदोन्नति में

वरिष्ठ अध्यापकों (द्वितीय श्रेणी) के शिक्षण विषयों में वाणिज्य के विषय न होना इसका बड़ा कारण है। वाणिज्य स्नातक अभ्यर्थी थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती में तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन सैंकंड ग्रेड भर्ती में नहीं। यही नहीं थर्ड ग्रेड शिक्षक के पद पर नियुक्त ऐसे शिक्षकों के लिए आगे पदोन्नति भी लगभग नामुमकिन हो जाती है।

अन्याय हो रहा है

वाणिज्य स्नातक विषय शिक्षकों के साथ 25 वर्षों से अन्याय हो रहा है। सरकार चाहे तो तृतीय श्रेणी के वाणिज्य शिक्षकों को पदोन्नत कर मिडिल स्कूल हैडमास्टर पद पर या प्रत्येक सीनियर विद्यालय में हैड टीचर की पोस्ट सृजित कर प्रमोशन दे सकती है।

विजय झुंझिया, प्रदेशाध्यक्ष,
राजस्थान वाणिज्य शिक्षा संघर्ष समिति

पदों के आधार पर
होते हैं प्रमोशन

वाणिज्य विषय के पद कम होने के कारण यह समस्या आ रही है। जैसे जैसे पद खाली होंगे, उसी के अनुसार वाणिज्य के शिक्षकों का प्रमोशन भी हो जाएगा।

गोविन्दसिंह डोटसरा, शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक में नहीं मिली थी रिपोर्ट संतोषजनक

शिक्षा विभाग में दो डीडी पर गिरी गाज, भेजा निदेशालय

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

सीकर. समसा की समीक्षा बैठक में दो उपनिदेशक की कार्यशैली संतोषजनक नहीं पाए जाने पर विभाग ने दोनों को पद से हटाते हुए वापस मूल विभाग में भेज दिया है। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटसरा ने मंगलवार को समीक्षा बैठक में काम नहीं करने के बाद भी विभिन्न पदों पर जमे रहने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक

अभी कई पर और गिर सकती है गाज

समसा की पांच घंटे चली समीक्षा बैठक में कई अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। इसमें से दो अधिकारियों के खिलाफ बुधवार को विभाग ने एक्शन ले लिया। अभी कई अधिकारियों के कार्यों को और परखा जा रहा है। विभिन्न कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कई और अधिकारियों को भी वापस मूल विभाग में भेजा जा सकता है।

अभिषेक भगोतिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत उपनिदेशक कृष्ण अवतार शर्मा व प्रदीप उपाध्याय को परिषद से कार्यमुक्त

कर दिया है। दोनों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। परियोजना निदेशक ने दोनों के कार्यों को

कार्रवाई जारी

समीक्षा बैठक में कई अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी। ऐसे कर्मचारियों को वापस मूल विभाग में भेजा है। लापरवाही कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

गोविन्द सिंह डोटसरा,
शिक्षा मंत्री

संतोषजनक नहीं मानते हुए प्रतिनियुक्ति समाप्त की है। दो डीडी पर कार्रवाई होते ही शिक्षा विभाग में खलबली मच गई।

ई-
त
पत्र
राज
सी
मह
से
के
लि
जा
पार
में
के
रि
के
चु
ऑ
रहे
कि
प्रति
लॉ
सब
लि